<u>संपादकीय</u>

किसानों की संस्था होने के कारण हम लगातार पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते आ रहे हैं, कि कुछ लोग एकमत से सहमत हैं और कुछ लोग इस बात से असहमत हैं, वह है खाद्य असुरक्षा की धारणा और कारण रहित डर। इस मुद्दे को समझने के लिऐ इसका ऐतिहासिक कारण जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे दिलों में यह डर किस तरह से बैठा रखा है।

ऐतिहासिक पृ-ठभूमिः

क). हजारों व-र्ों से मानव जाति भोजन की तलाश में हमेशा रही है क्योंकि उसे अगला भोजन मिलने की गारंटी नहीं थी। मनु-य भोजन के प्रति तो हमेशा सचेत रहा किंतु आने वाले खतरों से अंजान रहा, इस कारण मनु-य ने यह मान लिया कि भोजन की कमी हो सकती है, लेकिन इसे अपवाद नहीं माना।

ख). व-र् 1770 के अकाल ने गंगा के समतल क्षेत्रों को संकट में डाला जिसके कारण 1 करोड़ से अधिक लोग अकाल का शिकार हुऐ थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिगो पौधे उगाने और अफीम की फसल लगाने के लिऐ खाद्य फसलों को उजाड दिया था और कृ-ि उत्पादों पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत लगान लगाया तथा चावल का भंडार रखने पर प्रतिबंध लगाया था। हर मौसम में भोजन की कमी होने के कारण आकाल पडा था क्योंकि सूखा पडा था।

ग). 1798 ऐ.डी. में थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, 'पॉप्यूलेश्न ऐन ऐसेय' में लिखा 'जनसंख्या की ाक्ति निश्चित रूप से भूमि पर उगने वाले अनाज से अधिक है, जिस कारण आदमी को अपना निर्वाह करने में अत्यधिक कठिनाई आऐगी, जिसका अर्थ है जनसंख्या वृद्धि हानिकारक सिद्ध होगी।

घ). व-र् 1943 में बंगाल में आकाल से ईस्ट इंडिया हिल गई और लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग मारे गऐ। इसका कारण था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत से सारा अनाज ले जाने का आदेश दिया तांकि वह दूसरे विश्व युद्ध में लडने वाली सेना के लिऐ अनाज का भंडार बना सके।

ड.). भारत द्वारा दूसरी पंचव-र्िय योजना में नितियां बदली - खाद्य पदार्थों की इतनी कमी हो गई थी कि व-र् 1960 में लाल बहादुर ाास्त्री को लोगों से 1 सप्ताह में 1 बार भोजन न करने की अपिल करनी पडी तांकि भूखे लोगों को अनाज मिल सके। अमेरिका से अनाज मंगाया गया और दूर-दूर के क्षेत्रों में जहाज से सिधा अनाज वहीं भेजा गया।

च). व-र् 1967 में विलियम और पाल पैडॉक ने एक किताब लिखी 'आकाल 1975! अमेरिका का निर्णयः कौन बचेगा?' इसमें कहा गया कि भारत जैसे कई देश इतने निराश और बेकार हैं कि उनके लिऐ अमेरिका की सहायता बैकार जाऐगी और उन्हें बचाया नहीं जा सकता, इस कारण उन्हें भूखा मरने के लिऐ छोड़ दिया जाऐ। क्योंकि इन देशों की अत्यधिक जनसंख्या है, अर्पायप्त कृ-ि उत्पादन है और राजनैतिक पहल भी दिखाई नहीं देती।

छ). एक अन्य मूर्ख अर्थशास्त्री बहुत लोकप्रिय हुऐ जिनका नाम था पॉल आर. ऐहरलिच जिन्होंने जनसंख्या बम पुस्तक लिखि उसमें भी मॉलथस और पैडॉक जैसे विचार ही प्रकट किऐ।

चाहे नीतिनिर्माता, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और राजनैता जो हमारे जिने और सुधार का निर्णय लेते हैं उनमें से अधिकतर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसी प्रकार का साहित्य का अध्यन्न किया और इससे प्रभावित हैं। ऐसे विद्वान यह मानते हैं कि देश के किसान पर्याप्त अनाज नहीं उगा सकते। जबकि तथ्य है कि पिछले 30 व-र्ों में अधिक समय तक भारत एक अनाज का बढ़ा निर्यात्क रहा है। दूसरी तरफ जिंस फर्मों, सट्टेबाजों,

व्यापारियों और गैर-सरकारी संस्थाओं का समूह है जो हमारे देश में अनाज की कमी होने का दुरप्रचार करता है ताकि वह लाभ कमा सकें। यह नीति या उनका लक्ष्य देश के कृ-ि क्षेत्र के लिऐ घातक भवि-यवाणी है।

इस प्रकार की ऐतिहासिक मुद्दे गलत साबित हुऐ हैं। सार्वजनिक खाद्य वितरण नीति और काम के लिऐ अनाज, नवीनतम तकनीक का उपयोग और कृ-ि हस्तक्षेप जैसे कार्यक्रमों से खाद्य उत्पादन और इसकी उत्पलबधता बढ़ी है, हालांकि यह स्थाई नहीं है।

समय बितने के साथ-साथ नऐ खतरे नजर आ रहे हैं, जिन पर ध्यान देना अनिवार्य है, वह है जलवायु परिवर्तन के परिणाम।

इन सब जोखिमों के होते हुऐ भी कई संभावनाओं को में नीचे स्प-ट कर रहा हूँ:

1- अनुसंधान केन्द्र और गांव में उत्तम खेत का उत्पादकता अंतर और प्रत्येक गाँव में उत्तम और बहुत खराब खेती के अंतर को कम करके 20 प्रतिशत तक उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
2- बेहतर बुआई और कटाई मशीनरी को उपलब्ध कराने और इसका उपयोग करके 20 प्रतिशत और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।
3- भूमि के 70 प्रतिशत भाग पर समुद्र है लेकिन वहां से केवल 2 प्रतिशत आहार मिलता है, जबकि इस 2 प्रतिशत आहार में विश्व की आवश्यकता अनुसार 16 प्रतिशत प्रोटीन मिलता है। मछलियों का ही नहीं बल्कि समुद्र की अन्य वनस्पति का भी भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है।
4- जिनौम ऐडिटिंग, करिस्पर तकनीक जैसी जैविक तकनीक लगातार अपनाई जा रही है, लेकिन इसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा। पौधों में पौ-ाक तत्व बढ़ाने के लिऐ 2 प्रतिशत धूप का केवल 0.2 प्रतिशत उपयोग ही हो पा रहा है, इसे बढ़ाया जा सकता है। पौधे हमें केवल 40 प्रतिशत तक का पौ-ाक तत्व देने के लिऐ तैयार हो पाते हैं, जबकि इसमें वृद्धि की जा सकती है। दिन प्रतिदिन इस तकनीक की कीमत कम हो रही है। उदाहरण के लिऐ पहली हयूमन जिनौम प्रौजेक्ट की कीमत रू. 500 करोड़ से अधिक थी, लेकिन आज इसी मशीनरी के जिन् का उपयोग केवल रू. 10,000/- में किया जा सकता है।
5- विश्व की 80 प्रतिशत जनसंख्या ृहरी क्षेत्रों में रह रही होगी और इनके लिऐ समतल कृ-ि एक नया क्षेत्र हो सकता है। अगले 25 व-र्ाों में इसे अपनाना ही पड़ेगा। ऐम्पायर ऐस्टैट जैसी 10 बिल्डींग से न्यूयॉर्क सिटी की आवश्यकता अनुसार कैलोरी उपलब्ध कराई जा सकती है और आने वाले समय में इसमें वृद्धि हो सकती है।
6- पशुओं के चारे के लिऐ 30 प्रतिशत भूमि और 50 प्रतिशत जल का प्रयोग किया जाता है। 10 किलो कैलोरिस से 1 किलो मीट बनता है जिस कारण अत्यधिक संसाधनों की हानि हो रही है। आने वाले 20 व-र्ाों में ऐसे हैमबर्गरस और मीट होगा जो पौधों के रस से अथवा प्रयोगशाला में तैयार किया जाऐगा जिसका स्वाद और ृाक्ति वास्तविक मीट जैसी ही होगी। यह एक सुचारू उपाय हो सकता है। ऐसा करने से बची हुई भूमि और जल का उपयोग अन्य क्षेत्रों अथवा प्रकृति को वापिस करने में किया जा सकेगा।
7- केवल 3 फसलें हमें हमारे कुल भोजन का 66 प्रतिशत भाग देती हैं, वह हैं, गेहूँ, मक्का और चावल। बाकि अन्य 8 फसलों से आता है। जबकि धरती पर 50 हजार से अधिक खाद्य पदार्थ या पौधें हैं।

हम इन 3 फसलों के पौधों का भी पूरा उपयोग नहीं करते हैं। हमें अपने भोजन में विविधता लानी होगी।

8- आज 30 प्रतिशत खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, इन्हें कम करके 10 प्रतिशत किया जा सकता है। इसके लिऐ बिना कुछ अधिक भूमि अथवा उपकरणों के अधिक भोजन मिल सकता है। ऐसा करने से अधिक भूमि भी उपलब्ध होगी जिस पर खेती या जंगल बनाऐ जा सकते हैं।

9- प्रोटीन का अगला स्रोत्र कीट या कीडे हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कई देश कीडों की खेती कर रहे हैं और लगभग 2 हजार खाने योग्य कीट होते हैं।

10- ृहरी क्षेत्रों में मानव अपशि-ट का उपयोग पौ-क तत्व और अधिक अनाज उगाने में किया जा सकता है।

11- माईक्रोबस अगला ऐसा क्षेत्र है, चाहे वह मनु-य से संबंधित हो अथवा पशु से, इससे अत्यधिक हानि होती है। दूध देने वाले पशुओं को कृमिनाशक दवा देने से भी दूध का उत्पादन 20 प्रतिशत बढ़ेगा।

हमने समस्या की गलत पहचान की है। न तो हम पिछले 10 हजार व-र्गों में अनाज की कमी झेल रहे थे, न ही भवि-य में कमी होगी। में जादू की छडी के उपाय को पसंद करता हूँ, किंतु यह उससे भी अधिक कठिन है। खाद्य असुरक्षा एक सांसकृतिक समस्या है जो कि मनु-य की आदतों के कारण है, न कि भूमि की जो हमें खाने के लिऐ पर्याप्त भोजन न दे सके। मानव क्षमता को कम आंकना एक इतिहास रहा है। दुनिया के अधिकतम लोग कुपो-क हो सकते हैं, लेकिन भूखे रहने वाले लोगों की संख्या उतनी ही होगी जितने दुनिया में मोटे लोग हैं।

सबसे महत्वपूर्ण निवेश यह है कि भोजन की असली लागत की गणना की जाऐ। लोगों की मेज तक पहुंचने की सही लागत को जाने बिना नीति निर्माता कभी भी कोई सुचारू और कारगर उपाय अथवा निवेश नहीं कर सकते। भारत सहित कई देशों में सरकारी नीतियां इस प्रकार से बनाई जाती हैं जो सरकारी लक्ष्यों के समान नहीं होती हैं। किंतु इतिहास का पन्ना बदलना संभाव है। हम एक ऐसा देश बन सकते हैं जहां अपना भाग्य हम स्वयं लिख सकते हैं।

<u>कृ-ि का कम वार्-िक उत्पादन कालेधन से भी अधिक बढ़ा खतरा है</u>

विजय सरदाना

बॉयो-ईकॉनोमी और ऐग्री बिजनैस वैल्यू चैन्स, ईनोवेशन मैनेजमेंट ऐण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग में विशे-ाज्ञ

बढ़ी हुई खाद्य मुद्रास्फीती, बढता आयात और कम होते निर्यात के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर होती जा रही है। भारत सरकार के वाणिज्यि विभाग ने कहा है कि कृ-ि आधारित जिंसों का आयात 2014-15 और 2015-16 में बढ़कर रू. 1,98,734/- हो चुका है और भारत ने इसके लिऐ रू. 2,58,324/- करोड़ की जिंसों का निर्यात बाजार भी खो दिया है। इसमें प्रति व-र् की दर से खाद्य पदार्थों की हानि और खराबी को जोडें तो यह आंकडा रू. 1,00,000/- करोड वार्-िक होता है। इस प्रकार कृ-ि क्षेत्र पर ध्यान न देने से पिछले व-र् भारत को रू. 1,50,000/- करोड की हानि उठानी पडी।

यह 1 व-र् में राजस्व हानि है, इसके अतिरिक्त किसानों को लाभकारी मूल्य न मिलने से अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने से किसान समुदाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अलग से प्रभावित हुई है। यह कालेधन कहीं अधिक देश को हानि है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा कि खाद्य मुद्रा स्फीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवम् पौ-िटकता पर कैसे पड़ रहा है जिसकी गणना नहीं की गई है। भारत के राजनैताओं ने एक बड़ा उपाय किया कि भारत में कालेधन के समाधान के लिऐ नोटबंदी जैसा कडा कदम उठाया। क्या ऐसा ही कडा उपाय देश की खाद्य सुरक्षा और कृ-ि के समाधान के लिऐ राजनैता करेंगे ?

कोई भी देश खाद्य सुरक्षा के बिना अपनी राजनैतिक सम्प्रभुता सुनिशिचित नहीं कर सकता। खाद्य सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि एवम् कानून और व्यवस्था का किसी भी समाज में निकट संबंध है। आर्थिक वृद्धि प्रत्यक्ष रूप में खाद्य मुद्रास्फीती पर निर्भर है। जितनी अधिक खाद्य मुद्रास्फीती होगी, उतनी ही कम आर्थिक वृद्धि होगी। भारत में प्रत्येक व-र् लगभग 1.5 करोड लोग बढ़ जाते हैं, जिन्हें पौ-ाक आहार की आवश्यकता होती है।

इन मूल तथ्यों को ध्यान में रखकर ऐसी कोई आशा नहीं है कि भवि-य में खाद्य मुद्रास्फीती कम होगी। हालांकि इसके लिऐ खाद्य उत्पादन, खाद्य आपूर्ति कार्यक्रम और जीवन ौली तथा उपभोग आदतों में सुधार करके इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। नीति निर्माता और देश की सरकार के लिऐ सबसे बडी चुनौती उत्पादन बढाना और खाद्य हानि को कम करना है तांकि अधिकतम लोगों तक सस्ता अनाज और खाद्य पदार्थ पहुंच सकें। आने वाले व-र्ों में भारत को कितने अनाज की आवश्यकता होगी ? यह सुनने में अच्छा है कि देश में अनाज की कमी नहीं है और खाद्य आपूर्ति भी अच्छे ढंग से हो रही है। किंतु भारत अब खतरे की रेखा तक पहुंच चुका है। यह उचित समय है कि वास्तविक समस्या को पहचानें और इसका उपाय करें, अथवा यह बहुत लेट हो जाऐगा।

1 अरब 27 करोड़ लोगों के देश में, जहां विश्व की औसत प्रति व्यक्ति आय से लोगों की आय बहुत कम है और जहां की 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है और 45 प्रतिशत बच्चे कुपो-ाण के शिकार हैं, अधिकतम बाल मृत्यु दर है, क्योंकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध की कमी है, जिस कारण वह नवजात शिशु को दुध नहीं पिला पाती और खाद्य मुद्रास्फीती अब भी है और हमेशा रहेगी, यही मुद्दा प्रत्येक चुनाव में सबसे बड़ा राजनैतिक मुद्दा होता है। कोई भी सत्तादल यही दावा करता है कि वह सत्ता में आते ही खाद्य मुद्रास्फीती को नियंत्रण में करेगा।

कृ-ि सुधारों में समय लगेगा, क्योंकि कोई भी सरकार अपने राजनैतिक हितों को त्याग नहीं सकती। नीति निर्माता आदतन ऐसी राजनैतिक रिश्वत मतदाताओं को खैरात के रूप में देते हैं तांकि वह चुनाव जितें, लेकिन कृ-ि सुधार के लिऐ कोई कारगर कदम नहीं उठाते। भारत की आर्थिक सफलता की यही मांग है कि राजनेता कृ-ि क्षेत्र पर पूरा ध्यान दें। इसके लिऐ दीर्घकालिक स्थाई नीति की ार्त होगी तांकि न्यूनतम खाद्य सुरक्षा सुनिशिचित की जा सके। खाद्य सुरक्षा योजना को विकसित करने की आवश्यकता है।

देश में एक रा-ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना होनी चाहिऐ जो नीजि निवेश्कों को निवेश करने के लिऐ प्रोत्साहित करे। इस योजना में भोजन की बढ़ती मांग और चारा, फाईबर और ईंधन की बढ़ती मांग पर विशे-ा ध्यान दिया जाऐ। इसका समाधान करने के लिऐ कृ-ि आधारित सभी क्षेत्रों पर विशे-ा ध्यान देने की योजना तैयार की जाऐ। इसके लिऐ अगले 10 से 15 व-ा की अवधि के लिऐ सभी सहभागियों को स्प-ट निर्देश दिया जाऐ और प्रत्येक व-ा इसका मूल्यांकन किया जाऐ, तांकि आने वाले परिणामों से किसी प्रकार के सुधारात्मक उपाय इस योजना में ामिल किऐ जा सकें। प्रश्न यह है कि जब भारत में सब कुछ ठीक है और खाद्य बाजार भी अच्छा है तो अधिकतम जिंसों का हमारा निर्यात क्यों कम है ?

एफ.ए.ओ. के अध्यन्न के अनुसार दक्षिण ऐशिया की जनसंख्या के लिऐ व-ा 2025 में 2,700 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत में इसकी दर लगभग 525 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन अनाज की है, जबकि चीन और अमेरिका में यह क्रमशः 980 ग्राम और 2,850 ग्राम है।

- यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति उपभोग 650 ग्राम है तो व-ा 2025 में इसकी आवश्यकता लगभग 390 मैट्रिक टन अनाज की होगी।
- दालों के मामले में व-ा 2025 में भारत को लगभग 35 मिलियन टन दालों की आवश्यकता होगी।
- प्रति व-ा 17 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति की दर से खाद्य तेल की लगभग 23.8 मिलियन टन तेल की जरूरत होगी।
- भोजन और चारे की कमी बहुत से क्षेत्रों में पहले से ही 35 प्रतिशत और 65 प्रतिशत के बीच है।

भारतीय कृ-ि में अधिकत किसान छोटे किसान हैं और उनके पास छोटे-छोटे खेत हैं। व-ा 1970-71 में भूमि स्वामित्व का आकार 2.30 हैक्टेयर था, जो व-ा 2000-01 में कम होकर 1.32 हैक्टेयर हो चुका है। जिस जमीन पर कृ-ि की जाती है उसका आकार 70 मिलियन से बढ़कर 121 हो चुका है। यदि ऐसा ही रूझान जारी रहा तो इसका औसत आकार व-ा 2020 में केवल 0.68 हैक्टेयर और व-ा 2030 में मात्र 0.32 हैक्टेयर रह जाऐगा। दूसरी तरफ 2025 तक प्रति व्यक्ति कृ-ि भूमि मात्र 0.1 हैक्टेयर प्रति व्यक्ति होगी। इस प्रकार आशंका है कि 1 व-ा के लिऐ अपने भोजन, ईंधन, चारे और फाईबर की दैनिक आवश्यकता को पूरा

करने के लिऐ प्रत्येक किसान के पास 100 फीट ग 100 फीट आकार का भूखंड रह जाऐगा। समय बीतने के साथ जनसंख्या बढ़ेगी और यह आकार बिलकुल सिकुड़ जाऐगा।

इसके अतिरिक्त अन्य कई चिंताजनक पहलू भी हैं। कृ-ि मंत्रालय का अनुमान है कि देश की लगभग 120.72 मिलियन हैक्टेयर भूमि में भू-कटाव और 8.4 मिलियन हैक्टेयर भूमि में भू-लवण्यता तथा पानी जमा होने की समस्या है। भारत में प्रत्येक व-र्ा 0.8 मिलियन टन नाईट्रोजन, 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस और 26.3 मिलियन टन पौटेश्यिम की हानि होती है। इस समस्या का ाीघ्र समाधान करना होगा। यह समस्या अत्यधिक गंभीर हो रही है जिसका कारण, पौ-टिकता की कमी और सूक्ष्म पौ-टिक तत्वों की क्षति होने से भूमि में उत्पादक तत्व कम होते जा रहे हैं, जिस कारण उत्पादकता में कमी आ रही है।

जल एक अन्य बढ़ी समस्या है। कृ-ि मंत्री के अनुसार 2025 तक भारत में प्रति व्यक्ति लगभग 1,700 ऐम3 की आवश्यकता होगी और इसका 84 प्रतिशत भाग का उपयोग सिंचाई के लिऐ किया जाऐगा, यह अत्यधिक गंभीर वि-ाय है।

- स्वतंत्रता के समय जनसंख्या 400 मिलियन से कम थी और प्रति व-र्ा प्रति व्यकित 5000 क्यूबिक मिटर जल उपलब्ध था।
- 2007 में भारत की जनसंख्या 95 करोड़ थी और जल कम होकर 2,200 क्यूबिक मीटर रह गया।
- 1 अरब का आंकडा पार करने के बाद जल की उपलब्धता कम होकर 2,000 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई।
- 2025 आते-आते यह दर कम होकर केवल 1,500 रहने का अंदेशा है अथवा 30 प्रतिशत जबकि स्वतंत्रता के समय से तुलना करने पर इसका स्तर देखा जा सकता है।
- 2025 में सिंचाई के लिऐ जल की आवश्यकता 790 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी, लेकिन भारत का कुल जलाश्य क्षमता 300 से 350 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी।
- प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2025 में जनसंख्या वृद्धि होने से गिरकर लगभग 1,500 क्यूबिक मीटर रह जाऐगी।
- इसका अर्थ है, भारत की मूल आवश्यकता आहार, चारा, सफाई, उद्योग और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिऐ, प्रति दिन प्रति व्यक्ति 4,000 लीटर जल की आवश्यकता होगी।
- पशुओं को भी जीवित रहने के लिऐ जल की आवश्यकता की गणना इसमें नहीं की गई है।

इसी बीच में भारत की आर्थिक वृद्धि होने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण पहले से ली जाने वाली भोजन सामग्री के स्थान पर लोग मांस और डेरी पदार्थों की ओर आकर्-ित हो रह हैं, जिनके उत्पादन के लिऐ अधिक जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिऐ 1 कि.ग्रा. चावल उगाने के लिऐ 3,500 लीटर जल और 1 कि.ग्रा. मीट के लिऐ 15,000 लीटर तथा 1 कप कॉफी के लिऐ 140 लीटर जल की आवश्यकता होती है। केवल 1 लीटर दूध के उत्पादन में लगभग 2,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगले 10 व-र्ाों में इस प्रकार की खुराक के लिऐ अत्यधिक जल की आवश्यकता होगी और यह रूझान 21वीं सदी के मध्य तक जारी रहेगा।

यह सब कारणों से समस्या कठिन और गंभीर हो रही है। अभी भारत एक खाद्य पदार्थों का बढा आयातक है और आने वाले व-ार्ें में और भी बढ़ा हो जाऐगा। लेखक का अनुमान है कि भरसक प्रयास करने के बाद भी भारत अपने खाद्य तेलों और दालों की आवश्यकता तथा पशुओं के लिऐ चारे की आवश्यकता हो पूरा नहीं कर पाऐगा। देश की ृवेत क्रांति पर भी विराम लग जाऐगा।

लेखक के अनुमान के अनुसार 2030 में भारत की अनाज और अन्य कृ-ि उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करने के लिऐ दोगुनी भूमि की आवश्यकता होगी, यदि खाद्य और अन्य कृ-ि जिंसों की उत्पादकता इसी स्तर पर रही। इसका विकल्प प्रति एकड में उत्पादकता को दोगुना करना अथवा खाद्य आपूर्ति के अन्य संसाधनों का पता लगाना है। अभी विद्यमान उपायों से इस गंभीर समस्या का समाधान करना एक बड़ी चुनौती है। खाद्य मुद्रास्फीती का बुरा प्रभाव कृ-ि क्षेत्र पर पडा है, जो कि एक अनिवार्य जिंस का क्षेत्र है। घरेलू मूल्यों को नियंत्रण करने के प्रयास का अर्थ है कि आयात बढ़ाना।

नीति निर्माताओं के लिऐ उपाय और सिफारिशें:

1. अपने राजनैतिक नारों को छोडकर वास्तिविक स्थिति को पहचाने कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है।
2. नोटबंदी की बाद भारत की खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देना प्रधानमंत्री का कार्य है और इस कार्य को किसी अन्य मंत्रालय को न दिया जाऐ, क्योंकि इस क्षेत्र पर पूरा ध्यान न देने से लोगों को अच्छे दिन दिखाने की योजना पर पानी फिर जाऐगा। व-ार् 2019 में खाद्य मुद्रास्फीती एक प्रमुख राजनैतिक मुद्दा बन जाऐगी।
3. जी.ऐस.टी. अनुभव से सिख लेते हुऐ भारत को एक रा-ट्रीय खाद्य सुरक्षा परि-ाद् बनानी होगी, क्योंकि कृ-ि सभी राज्यों का वि-ाय है, और जब तक सभी राज्य खाद्य सुरक्षा के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो केन्द्र सरकार की कोई भी पहल व्यर्थ साबित होगी।
4. एक बार जी.ऐस.टी. लागू हो जाने के बाद निधि आबंटन में खाद्य सुरक्षा और कृ-ि को प्रमुखता दी जानी चाहिऐ। इसका कारण लोगों की जिंदगी के लिऐ पौ-िटक तत्व अनिवार्य हैं और ृाहरी एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल एवम् अर्धकुशल लोगों के लिऐ रोजगार भी अनिवार्य है। कोई भी ऐसा उद्योग या तकनीक नहीं है जो 30 मिलियन लोगों को नौकरी दे सके और इसके लिऐ कम से कम 20 व-ार् और लगेंगे।
5. एक रा-ट्रीय कृ-ि तकनीक नीति तैयार करें, न की एक कृ-ि नीति ही। कृ-ि विश्वविद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिऐ जिम्मेवारी सौंपी जाऐ और इसके लिऐ यदि भारतीय कृ-ि अनुसंधान और कृ-ि विश्वविद्यालयों के लिऐ ृाासनादेशों में परिवर्तन करना पडे तो आने वाले बजट सत्र में इसे बदल दिया जाऐ।
6. नीति आयोग को राज्यवार एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिऐ और तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट भेजी जाऐ ताकि समय अथवा संसाधनों की क्षति न हो।
7. सरकार को एक बढ़ा कृ-ि आधारभूत ढ़ांचा तैयार करना चाहिऐ जो अनाज संबंधी ढांचे और संबंधित सुविधाओं पर ध्यान दे, तांकि कम से कम भोजन की क्षति हो और राजस्व भी बचाया जा सके।
8. कृ-ि और खाद्य पद्धति के प्रबंधन के लिऐ सैटेलाइट तकनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के उपयोग जैसे विकल्प अपनाऐ जाऐं।
9. कृ-ि विकास के लिऐ यदि पिछले व-ार् के राजस्व क्षति के 50 प्रतिशत भाग का निवेश भारत में किया जाऐ तो प्रत्येक व-ार् 50 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है।

10. खाद्य सुरक्षा और कृ-ि ही केवल ऐसे क्षेत्र हैं जो विश्वभर में भारत को एक राजनैतिक ाक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के बिना भारत विश्व में अपनी राजनैतिक रणनीति और आर्थिक ाक्ति को खो देगा।

व-र् 2017 रा-ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिऐ निर्णायक होगा। नीति निर्माताओं द्वारा भारत में एक सुविधाजनक स्थिति सुनिश्चित करने के लिऐ अभी अनाज का पर्याप्त भण्डार नहीं है।